हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 171 लखनऊ, रविवार 15 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

नौकरी की गारंटी होगी वानिकी विश्वविद्यालय की डिग्री : योगी

जंगल कौड़िया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कैम्पियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले वानिकी एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की डिग्री नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी होगी। विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा लेकर निकलने वाले युवाओं के लिए देश और दुनिया में रोजगार के व्यापक अवसर होंगे। विश्वविद्यालय अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।सीएम योगी शनिवार को जंगल कौड़िया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैम्पियरगंज में बने गिद्धराज जटायु संरक्षण केंद्र का उल्लेख करते हुए कहा कि कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारी जीवनशैली का हिस्सा है। गिद्धराज जटायु की मानव जाति पर बड़ी कृपा रही। माता सीता का हरण कर ले जा रहे रावण का पहला प्रतिकार गिद्धराज जटायु ने किया था। वह सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की सवारी भी हैं। आज केमिकल और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के चलते गिद्धराज की संख्या कम होती जा रही, वे मर रहे हैं। ऐसे में गिद्धराज के प्रति कृतज्ञता जताने और उनको संरक्षण देने के लिए कैम्पियरगंज में संरक्षण केंद्र बनाया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कैम्पियरगंज में प्रदेश का पहला वानिकी एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यहां युवाओं को जो डिप्लोमा व डिग्री मिलेगी, वह देश–दुनिया में नौकरी की गारंटी वाली होगी। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण प्रदूषण की है। वायु प्रदूषण से फेफड़े खराब होंगे और धीरे–धीरे पूरा शरीर खराब हो जाएगा। जब प्रदूषण नहीं होगा तो बीमारी भी नहीं होगी। उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की चर्चा करते हुए कहा कि वहां डॉक्टर दमा रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं। यह स्थिति पर्यावरण के साथ खिलवाड़ से बनती है। उत्तर प्रदेश में विकास भी है और दमघोंटू वातावरण से मुक्ति भी। कैम्पियरगंज में वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में और कारगर सिद्ध होगा। वनाच्छादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में वृद्धि का भी नया प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद प्रदेश और गोरखपुर के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि जब नीयत साफ हो तो परिणामअपने आप आ जाते हैं। अच्छी दिशा में किए गए प्रयास से आज गोरखपुर में खाद कारखाना चालू हो चुका है। गोरखपुर में एम्स सेवाएं दे रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा का उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। पिपराइच में चीनी मिल दोबारा चालू हो गई है। धुरियापार में कम्प्रेस्ड बायो गैस का प्लांट लग चुका है। गीडा में उद्योग ही उद्योग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश में विकास के बहुत बड़े–बड़े कार्य हो रहे हैं। विकास की सोच ही वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायक होगी मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया

ब्लॉक के हर गांव से जुड़ाव का जिक्र किया। वह यहां एक–एक गांव गए हैं। हर गांव की समस्या जानते हैं, समस्या समाधान के लिए संघर्ष किया है। बाढ़ की स्थिति में पानी में घुसकर लोगों तक पहुंचे हैं। समस्याओं की तस्वीर पहले से सामने थी तो लखनऊ से उन समस्याओं का समाधान करा दिया है। जंगल कौड़िया ब्लॉक व कैम्पियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आज विकास की जो स्थिति है, वह लोगों की कल्पनाओं से भी परे है। कालेसर–जंगल कौड़िया बाईपास बन जाने से लोग सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं, वह भी सिर्फ तीन–साढ़े तीन घंटे में। चिउटहा से कुशीनगर जाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। क्षेत्र की हर प्रमुख सड़क फोरलेन हो गई है। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो रहा है। जंगल कौड़िया में पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में डिग्री कॉलेज बन गया है। यहां 2 हजार से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है। स्टेडियम बन गया है। कुश्ती के प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा से क्षेत्र के पहलवानों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। विकास के साथ ही गरीबों के कल्याण के कार्य हुए हैं। आवास, शौचालय, राशन, आयुष्मान भारत, पेंशन का लाभ हर पात्र को उपलब्ध हुआ है। यह सब विकास के प्रति भाव रखने का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामपति यादव को भी श्रद्धापूर्वक याद किया। 1952 से आजीवन गोरक्षपीठ से जुड़े रहे रामपति यादव 1962 में जंगल कौड़िया के प्रमुख बने और तभी इस ब्लॉक मुख्यालय की स्थापना हुई थी। उन्होंने शालीनता और सहजता के साथ लंबे समय तक लोगों की सेवा की। मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख बृजेश यादव के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सवा करोड़ रुपये की ब्लॉक निधि और विकसित भारत जीरामजी योजना का बेहतर उपयोग किया है। ब्लॉक भवन में वातानुकूलित सभागार बनवाया है, सोलर पैनल की भी व्यवस्था की है। विकास के पैसे का ऐसा ही इस्तेमाल हो तो हर ब्लॉक चमकता दिखेगा। सीएम योगी ने भरोहिया ब्लॉक के विकास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जंगल कौड़िया के लोगों के साथ वह हमेशा खड़े हैं। विकास की हर मांग को वह पूरा करने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी ने लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पर्व शुभता का प्रतीक है। कैम्पियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, रोजगार, महिला सुरक्षा, जनकल्याण के कार्यक्रम नजीर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्यों की विस्तार से चर्चा की। सीएम की प्रेरणा और मंशा के अनुरूप एशिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीकैम्पियरगंज में बनने जा रही है। शीघ्र ही इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जंगल कौड़िया के ब्लॉक प्रमुख बृजेश यादव ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन से यह ब्लॉक विकास के पैमाने पर पचास साल आगे चल रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के चेयरमैन रमाकांत निषाद, भरोहिया के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरख सिंह, भाजपा के जिला मंत्री सदानंद शर्मा आदि उपस्थित रहे।

म्यूनिख में एस जयशंकर का दौरा : जी7 के विदेश मंत्रियों से मुलाकात में भारत के हितों पर चर्चा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जी7 समूह के विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। यहां उन्होंने भारत के यूएनएससी को सहयोग समेत साझा हितों पर बात की। जयशंकर ने एक्स पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने लिखा समुद्री संचार रेखाओं की सुरक्षा, सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले के तौर पर काम करना, बंदरगाह सुरक्षा को मजबूत करने और सबमरीन केबल संरचना के लिए मदद करने में हमारी भूमिका पर बल दिया। इस बातचीत में भारत और जी7 के बीच कई समानताएं और साझा हित पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही एस जयशंकर ने एक गोलमेज बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, म्यूनिख में आस्पेन के राउंडटेबल 'दिल्ली डिसाइड्स : मैपिंग इंडियाज पॉलिसी कैलकुलस' के साथ अहम बैठक की। बहुध्रुवीय मांगों को पूरा करने के लिए एक तेज और बेजोड़ विदेश नीति की जरूरत पर जोर दिया। इस संबंध में इंडिया–ईयू एफटीए और इंडिया–यूएस ट्रेड डील

के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। अनंता आस्पेन ने भी एक्स पोस्ट पर विदेश मंत्री का आभार जताते हुए जानकारी दी कि चर्चा में भारत की विकास रणनीति, मुख्य सहयोगी के सामने मौजूद विकल्प, और वैश्विक गतिशीलता में आए बदलाव के साथ सामरिक स्वायत्तता क्यों एक स्थिर सहारा बनी हुई है। अनंता आस्पेन सेंटर भारत में स्थित एक प्रमुख गैर–लाभकारी और गैर–पक्षपाती संगठन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। यह मूल्य–आधारित नेतृत्व और भारत के विकास से जुड़े सामरिक–आर्थिक और भू–राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देता है। यह आस्पेन इंस्टीट्यूट, यूएसए, और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से काम करता है।

स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 6 को किया अरेस्ट

बीएनई / नोएडा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ टीम ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले संगठित साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। नोएडा के स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ई–मेल केस में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टीम ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। यूपी एसटीएफ ने नोएडा से एक संगठित साइबर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी कर रहा था। यही गिरोह नोएडा के स्कूलों को धमकी भरे ई–मेल भेजने के मामले में भी शामिल पाया गया है। जांच में सामने आया कि 23 जनवरी 2026 को गौतमबुद्ध नगर के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ई–मेल मिले थे। इस मामले में साइबर क्राइम थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच में पता चला कि धमकी भरा मेल एक रिकवरी ई–मेल से जुड़ा था, जिसकी लोकेशन गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में मिली। एसटीएफ टीम ने जब छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ नेपाल और बिहार मूल के हैं, तो कुछ आरोपी ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से बीबीए,एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी टेक सपोर्ट और कॉल सेंटर का अनुभव रखते थे और 2023 से सक्रिय थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनंत कुमार (आगरा), अमीष जंग कारकी (नेपाल), दिव्यांशु (बिहार), लेखनाथ शर्मा (नेपाल), केदारनाथ (नेपाल) और साहिल कुमार (बिहार) के तौर पर हुई है।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा, आईआईएम गुवाहाटी और राष्ट्रीय डेटा सेंटर का किया उद्घाटन

एजेंसी

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी की शुरुआत की और एक उच्च तकनीक वाले डेटा केंद्र का उद्घाटन किया जो पूरे पूर्वोत्तर की जरूरतों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से गुवाहाटी आईआईएम के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पिछले साल गुवाहाटी में एक आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह पूर्वोत्तर में दूसरा और देश का 22वां आईआईएम है।

भारत–अमेरिका व्यापार मुद्दे पर निशिकांत दुबे ने दी राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती

एजेंसी

नयी दिल्ली/रांची। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों, कपास आयात और उसके भारतीय किसानों व वस्त्र उद्योग पर प्रभाव को लेकर खुली सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि वह भारत–अमेरिका व्यापार और टैरिफ संरचना को लेकर बड़ा झूठ फैला रहे हैं।

मुंबई में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का गिरा स्लैब, एक व्यक्ति की मौत, तीन घायल

बीएनई

मुंबई। मुंबई के मुलुंड इलाके में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाइन–चार के पुल का स्लैब कुछ वाहनों पर गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोपहर बाद एलबीएस रोड पर जॉनसन एंड जॉनसन फैक्टरी के पास गर्डर पुल की पैरापेट दीवार का एक स्लैब एक ऑटो रिक्शा और स्कोडा कार पर गिर गया, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

दमकल विभाग के अधिकारी ने मृतक की पहचान रामधन यादव और घायलों की पहचान राजकुमार इंद्रजीत यादव (45), महेंद्र प्रताप यादव (52) और दीपा रुहिया (40) के रूप में की। अधिकारियों ने बताया कि राजकुमार की हालत गंभीर है और उसे पास के अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है, जबकि महेंद्र व दीपा की स्थिति स्थिर बताई गई है। मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास

प्राधिकरण ने बताया कि दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर पियर–196 के पास, मुलुंड दमकल केंद्र के नजदीक दीवार का एक हिस्सा वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिर गया। मेट्रो परियोजना की टीम बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुटी है। इस हिस्से के ढहने के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। दक्षिण–मध्य मुंबई के वडाला से पड़ोसी जिले ठाणे तक लाइन–चार का निर्माण किया जा रहा है और इसका बड़ा हिस्सा घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले एलबीएस रोड के ऊपर से गुजरता है।

सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, आधुनिक युद्ध और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन पर मंथन

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 से 19 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक साझेदारी को नई दिशा देना है। यात्रा के दौरान आधुनिक युद्ध, मल्टी–डोमेन ऑपरेशन और संयुक्त सैन्य क्षमता बढ़ाने पर फोकस रहेगा। यह दौरा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बढ़ते सुरक्षा सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में साझा सुरक्षा हित, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। सिडनी में वह फोर्सेस कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और सेकंड डिवीजन के अधिकारियों से मिलेंगे। इन बैठकों को विशेष सैन्य अभियानों और कमांड स्तर के तालमेल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैनबरा में होगा गार्ड ऑफ ऑनर

कैनबरा में सेना प्रमुख का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उन्हें गार्ड

ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों अधिकारी 2015 में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में साथ पढ़ चुके हैं। इस व्यक्तिगत परिचय को रक्षा सहयोग के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। बैठक के बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल मुख्यालय में गोलमेज चर्चा होगी, जिसमें सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य के युद्ध अभियानों पर विचार होगा।

मल्टी–डोमेन और ज्वाइंट ऑपरेशन पर खास जोर

जनरल द्विवेदी ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। वहां उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं की एकीकृत और मल्टी–डोमेन ऑपरेशन क्षमता की जानकारी दी जाएगी। वह ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज के कमांडर से मिलेंगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार समन्वय और रणनीति को मजबूत करना है।

पूर्व सैनिकों से करेंगे मुलाकात

दौरे के दौरान सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और रक्षा विभाग के सचिव से शिष्टाचार भेंट करेंगे। हाल के समय में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैन्य कूटनीति को तेज किया है और वह यूएई व श्रीलंका का दौरा भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया यात्रा को हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा, प्रदेश में शुरू हुआ प्रशिक्षण महाभियान, बूथ मजबूत करने की कोशिश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाकर पार्टी की नीतियां प्रभावी ढंग से पहुंचाने का मंत्र दिया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रशिक्षण महाभियान के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जिस दिन सीखना बंद

होगा, उसी दिन आपका विकास भी रुक जाएगा। धनखड़ ने प्रशिक्षण महाअभियान को संगठन सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह भाजपा को बूथ स्तर तक और अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावी बनाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त, अनुशासित और सेवा भाव से ओत–प्रोत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रशिक्षण महाअभियान के माध्यम से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यपद्धति, सरकार की नीतियों और जनसेवा के मूल मंत्र से जोड़ा जा रहा है। इससे संगठन की मजबूती, विस्तार और अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर सिद्ध होगा। बनाई गई योजना प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रशिक्षण महाअभियान को संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बूथ स्तर तक सक्रिय और प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं। प्रशिक्षण महाभियान के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग तीन दिन का होगा। जबकि जिला स्तर पर दो दिन व मंडल स्तर चौबीस घंटे की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जबकि बूथ स्तर पर दो सत्रों में वर्ग आयोजित किए जाएंगे।

कार के अंदर युवक–युवती के शव मिलने से हड़कंप, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका

बीएनई

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर–39 थाना के अंतर्गत सेक्टर 107, दादरी रोड पिलर नंबर 84 के पास शनिवार को एक कार से युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सेक्टर–39 की थाना पुलिस और निरीक्षण टीम मौके पर पहुंची और कार का निरीक्षण किया। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सेक्टर 39 थाना पुलिस को सूचना मिली कि कार सड़क किनारे खड़ी है जो अंदर से लॉक है और वाहन के भीतर युवक और युवती के सिर में गोली लगी है। जबकि युवक के हाथ में पिस्टल भी है। पुलिस ने

कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान सुमित (32) पुत्र राजवीर और रेखा (26) पुत्री देवचंद के रूप में हुई है। सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी और रेखा नोएडा सेक्टर–101 सलारपुर की रहने वाली है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारी और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

संपादकीय

पुलवामा हमले से उपजा राष्ट्रीय संकल्प

14 फरवरी, 2019 के दिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों में से एक ने आत्मघाती हमलावर बन कर जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सेना के काफिले पर पुलवामा जिले के लेथपोरा में एक वाहन में सवार होकर भीषण आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 76वीं बटालियन के 40 जवान शहीद हो गए। हमलावर पुलवामा जिले का ही रहने वाला पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मद से जुड़ा स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार था। पुलवामा के लेथपोरा क्षेत्र में जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सी.आर.पी.एफ. के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था और सैंकड़ों जवान (लगभग 2500) ड्यूटी पर लौट रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को जवानों की बस से टक्कर मार दी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास का क्षेत्र दहल उठा। कई जवान मौके पर ही शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। यह केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास था। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद ने ली। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से इंकार किया। आतंकवाद का चरित्र कायरतापूर्ण होता हैकृवह छिपकर वार करता है और निर्दोषों की जान लेता है। पुलवामा ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सीमा पार से पोषित आतंकवाद केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती है। हमले की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। गांवों और शहरों में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जब शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गृह राज्यों में पहुंचे, तो हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर आंख नम थी, लेकिन हर हृदय में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। शहीदों के परिवारों ने अपने प्रियजनों की शहादत पर गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था दिखाई। यह भारतीय संस्कृति और संस्कारों की महानता का प्रतीक है। इस भीषण हमले में उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 5, पंजाब के 4, बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 2–2, असम, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश से 1–1, कुल मिलाकर 40 वीर जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस घटना की विश्व भर में निंदा हुई और कई देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन किया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को इसका दोषी मानते हुए कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस ले लिया ।पुलवामा हमले के बाद भारत की मोदी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरोंध् ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश थी। इसके अगले दिन 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई तनाव की स्थिति बनी, जिसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 1 मार्च, 2019 को उन्हें भारत को लौटा दिया गया। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश–ए–मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। इसे भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा गया। आज, पुलवामा की याद हमें केवल शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प के लिए भी प्रेरित करती है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोरता बरतना आवश्यक है, पर उतना ही आवश्यक है सामाजिक सौहार्द, युवाओं को सकारात्मक दिशा और विकास की मुख्यधारा से जोडना। पुलवामा हमला एक काला अध्याय अवश्य है, परंतु इससे उपजा राष्ट्रीय संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें निरंतर सतर्क रहने, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की प्रेरणा देती है। शहीदों का बलिदान केवल स्मृति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है,एक सुरक्षित, सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण की जिम्मेदारी।

राशिफल

मेष :– भावुकता वश संबंधों में भावनात्मक शोषण की आशंका है। पूर्वाग्रह वश अपने निकटस्थ सम्बन्धों के बारे में गलत धारणा पालना ठीक नहीं। सम्बन्धों की मधुरता हेतु आपस में विास कायम करें।
बृषभ :– व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिश्रम से आर्थिक लाभ के योग हैं। अत्यधिक भावुकता से भावनात्मक शोषण की भी आशंका है। भौतिक जगत से प्रभावित मन भविष्य को लेकर चिन्तित होगा।
मिथुन :– किसी अचल सम्पत्ति क्रय हेतु प्रयत्न तीव्र। अपने भाग्य को कोसना छोड़ अपने समय का सकारात्मक दिशा में लगावें। मान–प्रतिष्ठा में बृद्धि तो होगी परन्तु इससे अभिमानी न बनें।
कर्क :– समाजिक मान–सम्मान व वर्चस्व में बृद्धि होगी। व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिभा में निखार आयेगा। आपके स्थितियों में आकस्मिक सुधार के आसार बन रहें। कल्पनाएं साकार होती नजर आएंगी।
सिंह :– नये कायरे में पूंजी निवेश हेतु धनाभाव अवरोधक होगा। आपमें दूसरों को आकर्षित करने की अभूतपूर्व क्षमता है इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी।
कन्या :– रोजगार के क्षेत्र में किये गये कर्म का फल सफलता का आगाज कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिन्तित होगा।
तुला :– प्रणय सम्बन्ध में केन्द्रित मन प्रियतम से मिलने के लिऐ ब्याकुल होगा। किसी खास मुद्दे को लेकर परिजनों के मतभेद का सामना करना पड़ेगा। प्रयासरत क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी।
वृश्चिक :– अच्छे अवसरों का लाभ उठानें में सक्षम बनें। जीवन में नीरसता को कम करने के लिए मन को सकारात्मक दिशा देवें। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता से मन उत्साहित होगा।
धनु :– भावुकतावश किसी सम्बन्धी की बातें मन को कष्ट पहुचा सकती हैं। अपने अन्दर नए उर्जा की अनुभूति करेंगे। लेकिन बिगड़े हुए सम्बन्धों को सुधारने की चेष्टा करें। कार्य क्षेत्र में नये आसारों से उत्साहित होंगे।
मकर :– उच्छृंखल व मजाकिया स्वभाव आस–पास के वातावरण में महत्ता तो बढ़ाएगा। रोजगार में अपनी स्थिति को लेकर मन में हीनता का वाश होगा। महत्वपूर्ण पारिवारिक दायित्वों के पूर्ति के आसार बनेंगे।
कुंभ :– परिवार में किसी की अस्वस्थता से मन चिन्तित होगा। परिवारिक जिम्मेदारियां मन को बोझिल करेंगी। कोई अवरोधित काम के प्रति मन विशेष रूप से चिन्तित होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में प्रयत्न सार्थक होगा।
मीनः– सरल व मिलनसार स्वभाव से संबंधों में लोकप्रिय होंगे। भौतिक सुख–साधनों की लालसा में व्यय के योग हैं। जीविका क्षेत्र में परिश्रम सार्थक होगा। भावना प्रधान मन जल्द ही दूसरों से प्रभावित हो जाता है।

चुनाव के बाद चुप्पी : क्या राइट टू रिकॉल समय की मांग है?

-डॉ0 सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं। चुनाव इसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जिनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। किंतु व्यवहार में यह आदर्श अक्सर कमजोर पड़ता दिखाई देता है। चुनाव से पहले नेता जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, जनसभाएँ करते हैं, समस्याएँ सुनते हैं और बड़े–बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और सत्ता मिलती है, वही नेता जनता से दूर हो जाते हैं। धीरे–धीरे स्थिति ऐसी बन जाती है कि जनता अपने ही प्रतिनिधियों से मिलने और अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। यही वह विरोधाभास है जिसने "राइट टू रिकॉल" जैसे विचार को जन्म दिया है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने का एकमात्र प्रभावी साधन अगला चुनाव होता है, जो प्रायः पाँच वर्ष बाद आता है। यदि इस अवधि के दौरान कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, जनता की समस्याओं की अनदेखी करे या अपने चुनावी वादों से पूरी तरह मुकर जाए, तो जनता असहाय बनी रहती है। यह असहायता लोकतंत्र में निराशा और अविश्वास को जन्म देती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्या उसे प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? "राइट टू रिकॉल" इसी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करता, जनता के विश्वास को तोड़ता है या लगातार जनविरोधी कार्य करता है, तो जनता एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सके। यह अवधारणा लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधिक नहीं रहने देती, बल्कि उसे वास्तविक अर्थों में जवाबदेह बनाती है। इससे प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता के प्रति बनी रहती है। दुनिया के कई हिस्सों में इस विचार को व्यवहार में लाया गया है। उदाहरणस्वरूप, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा मजबूत मानी जाती है, जहाँ नागरिकों की भूमिका केवल प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहती। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर रिकॉल चुनावों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की व्यवस्था मौजूद है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि "राइट टू रिकॉल" कोई अव्यावहारिक कल्पना नहीं, बल्कि एक कार्यशील लोकतांत्रिक उपाय है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पंचायत स्तर पर कुछ राज्यों में सरपंच या स्थानीय प्रतिनिधियों को हटाने की सीमित व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, किंतु विधायक और सांसद जैसे उच्च पदों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कई बार जनता को पाँच वर्षों तक ऐसे प्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, जो न तो सदन में सक्रिय रहते हैं और न ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। भारत में "राइट टू रिकॉल" की मांग समय–समय पर उठती रही है।

इसके समर्थकों का मानना है कि यह व्यवस्था नेताओं में निरंतर जवाबदेही का भाव पैदा करेगी। जब प्रतिनिधि को यह ज्ञात होगा कि जनता चाहे तो उसे पद से हटा सकती है, तब वह जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, सत्ता के दुरुपयोग की प्रवृत्ति कम होगी और लोकतंत्र केवल औपचारिक न रहकर जीवंत बनेगा। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार जनता को केवल मतदाता नहीं, बल्कि सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। हालाँकि इस अवधारणा के आलोचक भी कम नहीं हैं। उनका तर्क है कि "राइट टू रिकॉल" से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। बार–बार रिकॉल की कोशिशें सरकारों को अस्थिर कर सकती हैं और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि विपक्षी दल या प्रभावशाली हित समूह इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं और जनभावनाओं को भड़काकर निर्वाचित सरकारों को गिराने का प्रयास कर सकते हैं। तात्कालिक असंतोष या अफवाहों के आधार पर लिया गया निर्णय दीर्घकालिक नीतियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें आधार बनाकर "राइट टू रिकॉल" की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि इसे संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। यदि रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के लिए मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन अनिवार्य किया जाए, कार्यकाल के शुरुआती और अंतिम चरणों में इस पर रोक लगाई जाए और पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र तथा पारदर्शी संस्थाओं द्वारा संचालित हो, तो दुरुपयोग की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। लोकतंत्र कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है; यह समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता रहता है। जिस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार, सूचना का अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े सुधारों ने लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया, उसी प्रकार "राइट टू रिकॉल" भी लोकतांत्रिक विकास की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। आज जब जनता पहले से अधिक जागरूक है, सूचना तक उसकी पहुँच व्यापक है और वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, तब लोकतंत्र में जवाबदेही के नए औजारों की मांग स्वाभाविक है। अंततः "राइट टू रिकॉल" कोई चमत्कारी समाधान नहीं है, लेकिन यह उस समस्या को अवश्य संबोधित करता है जिसमें चुनाव के बाद जनता और नेता के बीच दूरी बढ़ जाती है। यह अवधारणा नेताओं को यह स्मरण कराती है कि सत्ता स्थायी अधिकार नहीं, बल्कि जनता की अमानत है। यदि इसे संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर, चरणबद्ध और संतुलित रूप में लागू किया जाए, तो यह लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बना सकती है। एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहाँ जनता केवल वोट डालने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सत्ता को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता भी रखे।

छात्रों और चूल्हे के बीच खड़ी शिक्षिका

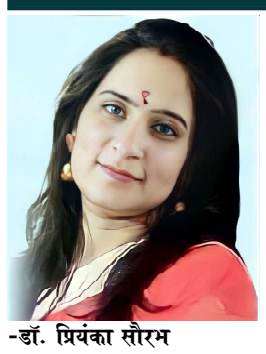

-डॉ. प्रियंका सौरभ

समाज में कुछ धारणाएँ इतनी गहरी पैठ बना लेती हैं कि वे सवालों से परे सत्य मान ली जाती हैं। "अध्यापिका की नौकरी तो सबसे आराम की है"कृयह वाक्य भी ऐसी ही एक सामाजिक मान्यता है, जिसे दोहराते हुए लोग शायद कभी ठहरकर यह नहीं सोचते कि इसके पीछे कितनी अधूरी समझ और कितनी गहरी उपेक्षा छिपी है। महिला शिक्षिका का जीवन इस धारणा का सबसे सशक्त, लेकिन सबसे कम सुना गया प्रतिवाद है। एक महिला शिक्षिका का दिन अलार्म की आवाज़ से नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारियों की सूची से शुरू होता है। घर के बाकी सदस्य अभी नींद में होते हैं, तब वह चाय चढ़ा रही होती है, टिफ़िन पैक कर रही होती है, बच्चों को जगा रही होती है और यह सुनिश्चित कर रही होती है कि रसोई में कुछ भी अधूरा न रह जाए। उसके लिए सुबह की तैयारी केवल खुद को तैयार करना नहीं, बल्कि पूरे घर को "चलने लायक" बनाना है। इसके बाद वह अपने पेशेवर चेहरे के साथ घर से निकलती है, लेकिन उसकी चिंताएँ दरवाज़े पर रुकती नहीं हैं। गैस बंद हुई या नहीं, गीजर का स्विच ऑफ है या नहीं ये सवाल बस या ऑटो की भीड़ में भी उसके साथ चलते हैं। विद्यालय पहुँचते ही उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः एक "आदर्श शिक्षिका" में बदल जाए। उसकी घरेलू थकान, निजी उलझनें और भावनात्मक दबावकृसबको जैसे विद्यालय के गेट पर ही छोड़ देना अनिवार्य है। वहाँ उसे मुस्कुराना है, संयमित रहना है, बच्चों के सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर देना है और हर परिस्थिति में खुद को संतुलित दिखाना है। यह भावनात्मक श्रम, जिसे न वेतन पर्ची में गिना जाता है और न ही किसी मूल्यांकन में, उसकी नौकरी का सबसे भारी और सबसे अदृश्य हिस्सा है। विडंबना यह है कि विद्यालय के भीतर भी समानता का दावा अक्सर अधूरा साबित होता है। खाली पीरियड, जिसे आराम या आत्मविकास का समय माना जाना चाहिए, महिला शिक्षिका के लिए प्रायः कॉपियों के ढेर, रिकॉर्ड्स की फाइलें और अतिरिक्त जिम्मेदारियों में बदल जाता है। दूसरी ओर, यही समय कई पुरुष सहकर्मियों के लिए अनौपचारिक चर्चाओं, चाय की चुस्कियों या विश्राम का अवसर बन जाता है। यह अंतर किसी लिखित नियम में दर्ज नहीं है, लेकिन व्यवहार में गहराई से मौजूद है। शाम को जब वह घर लौटती है, तो उसकी दूसरी पारी शुरू होती है। अब वह शिक्षिका नहीं, बल्कि रसोइया, देखभालकर्ता, प्रबंधक और हर समस्या की समाधानकर्ता बन जाती है। उसके कंधे पर बैग का बोझ और हाथों में सब्ज़ियों की थैलियाँ होती हैं, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि चेहरे पर थकान की एक रेखा भी न दिखे। क्योंकि अगर थकान दिखी, तो ताना तैयार है "कहा था न, तुमसे नहीं हो पाएगा।" सबसे पीड़ादायक क्षण तब आता है, जब वह कभी अपने बोझ को शब्दों में ढालने की कोशिश करती है। "अगर इतनी दिक्कत है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती?" यह वाक्य सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके भीतर स्त्री की शिक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा और उसके आत्मसम्मान का गहरा अवमूल्यन छिपा है। यह मान लिया जाता है कि उसकी नौकरी एक विकल्प है, एक शौक है, जिसे वह चाहे तो छोड़ सकती है।इयह भुला दिया जाता है कि उसकी डिग्रियाँकृएम.ए., बी.एड. और उनके पीछे की रात–रात भर की मेहनतकृसिर्फ़ सजावट नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व और पहचान का हिस्सा हैं। यह प्रश्न भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या आज भी एक महिला की उच्च शिक्षा को केवल "अच्छी शादी" और "संस्कारवान बच्चों" तक सीमित करके देखा जाएगा? क्या उसकी बौद्धिक क्षमता और पेशेवर योगदान का मूल्य केवल तब तक है, जब तक वह पारिवारिक अपेक्षाओं से टकराता नहीं? ये सवाल केवल शिक्षिकाओं के नहीं, पूरे समाज के हैं। आज के आर्थिक यथार्थ में महिला शिक्षिका की नौकरी कोई विलासिता नहीं है। बढ़ती महँगाई, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और स्वास्थ्य खर्चकृइन सबके बीच उसका वेतन परिवार की रीढ़ बन चुका है। वह नौकरी इसलिए नहीं करती कि उसे घर से भागना है, बल्कि इसलिए करती है ताकि उसका घर सम्मान और स्थिरता के साथ चल सके। इसके बावजूद, उसकी कमाई को

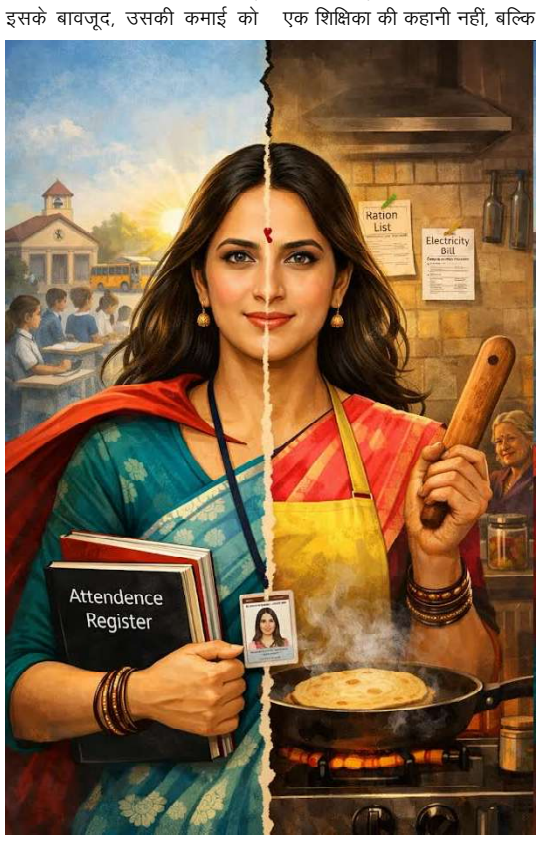

अक्सर "सहायक आय" कहकर छोटा कर दिया जाता है, मानो उसका योगदान वैकल्पिक हो। भावनात्मक स्तर पर भी उसका संघर्ष कम नहीं है। सबको समय देने की कोशिश में वह खुद से सबसे ज़्यादा समझौता करती है। बच्चों के प्रोजेक्ट, छात्रों की कॉपियाँ, परिवार की ज़रूरतें और सामाजिक अपेक्षाएँकृइन सबके बीच उसके अपने सपने, उसकी थकान और उसकी इच्छाएँ कहीं पीछे छूट जाती हैं। आईने में झलकते सफ़ेद बाल और आँखों के नीचे के काले घेरे उसे याद दिलाते हैं कि जिस परफेक्शन की दौड़ में वह लगी रही, उसने उसे खुद से दूर कर दिया। फिर भी, अगली सुबह अलार्म बजते ही वह फिर उठेगी। यह उसकी विवशता भर नहीं, उसकी ताकत भी है। लेकिन इस ताकत को स्वाभाविक मान लेना सबसे बड़ी भूल है। समाज को यह समझना होगा कि महिला शिक्षिका का धैर्य असीम नहीं है और उसका समर्पण शोषण का आधार नहीं बन सकता। यह संपादकीय किसी एक शिक्षिका की कहानी नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं की सामूहिक गाथा है। यह एक आह्वान है कृ नीतिनिर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और स्वयं समाज सेकृकि वे महिला शिक्षिकाओं के श्रम को सिर्फ़ स्वीकार ही न करें बल्कि उसका सम्मान भी करें। सहायक नीतियाँ, समान कार्य–वितरण और सबसे बढ़कर संवेदनशील दृष्टि विकसित करना आज की अनिवार्य आवश्यकता है। अंततः, शिक्षिका वह नींव है जिस पर पीढ़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर वही नींव थकी हुई, उपेक्षित और अनसुनी रहेगी, तो समाज की इमारत कैसे मजबूत होगी? यह समय है कि हम शिक्षिकाओं को केवल "समर्पित" कहकर आगे न बढ़ जाएँ, बल्कि उनके जीवन की वास्तविकताओं को समझेंकृऔर उन्हें वह सम्मान दें, जिसकी वे वास्तव में हक़दार हैं।

डाक्टरी सेवाओं में लूट की जिम्मेदारी सरकार पर

-पूरन चंद सरीन

कहावत है कि धन की हानि चिंता का विषय नहीं लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं तो यह घातक है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन सेहतमंद शरीर गंवा दिया तो उसे दोबारा पाना संभव नहीं। जीवन भर डाक्टरों की निगरानी और दवाइयों का सहारा जरूरी हो जाने से जीवन बोझ बन जाता है। डाक्टर बनने की अलौकिक कथा रू मैडीकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है और उनकी पढ़ाई के लिए उपलब्ध कालेज भी गत 10 वर्षों में लगभग दोगुने हो गए हैं। शानदार बिल्डिंग, आलीशान कमरे और अन्य निर्माण दिखाकर डाक्टरी पढने के इच्छुक विद्यार्थियों को मोटी फीस लेकर एडमिशन दे दिया जाता है। बढिया टाइम टेबल बना दिया और अब जब वे क्लासरूम या लाइब्रेरी या लैबोरेटरी में गए तो वहां न तो शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं और न ही लैब टैक्नीशियन या विशेषज्ञ जो टैस्ट आदि करने की विधि सिखा सकें। यह विडंबना नहीं बल्कि खिलवाड़ है कि मैडीकल की पढ़ाई के लिए सही शिक्षक न मिले तो प्रबंधकों ने किसी अन्य विषय में पी.एच–डी. करने वालों को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया क्योंकि कहलाते तो वे भी डाक्टर ही हैं। चिकित्सा शिक्षा में शिक्षकों की कमी को लेकर जनवरी 2026 में एक याचिका की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इन शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से शिक्षकों और प्रबंधन के खाली पदों पर अगले 4 महीनों में नियुक्ति हो जानी चाहिए। निश्चय ही यह नहीं हो सकता क्योंकि जैसी कछुआ चाल हमारे देश में है, उसमें यह असंभव है। उसके बाद और अधिक समय मांगा जाएगा जिसकी कड़ी वर्षों तक खिंचती चली जाएगी क्योंकि सरकार की कोशिशों में गंभीरता और पारदर्शिता नहीं है। वह असली–नकली आंकड़ों के आधार पर जनता को भ्रम में डाले रखती है वरना सोचिए कि इस बात में क्या तुक है कि पढ़ाने वाले हैं नहीं और पढने वालों को दाखिला दे दिया! हर साल मैडीकल में दाखिलों की सीटें बढ़ रही हैं और आने वाले वर्षों में जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रश्न यह है कि क्या कालेजों और शिक्षकों की जरूरत पूरी करने की व्यवस्था की जा रही है? जी नहीं, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। फैकल्टी की कमी विशेषकर तेलंगाना, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में नए खुले सरकारी कॉलेजों में 50 प्रतिशत तक है। जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं। इस कारण जहां शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ पडने से पढ़ाई की क्वालिटी गिर रही है, वहीं मामलों में अनक्वालीफाइड तथा नॉन मैडीकल फैकल्टी विद्यार्थियों का भविष्य तबाह कर रही है। जब ये मरीजों का इलाज करेंगे तो क्या होगा, सोचकर भी डर लगता है। क्या लोगों का जीवन खतरे में डालने वाले डाक्टर पैदा होने से देश का भला होगा? जाति आधारित आरक्षण के कारण दाखिला देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता समाप्त करना घातक है। नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी स्वयं की है उतनी ही स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए सरकार की है। बड़े शहरों में तो फिर भी गनीमत है लेकिन गांव–देहात और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं नदारद हैं। इन इलाकों में अगर कानूनन सर्विस करने की मजबूरी न हो तो कोई भी डाक्टर यहां न आए। इसका कारण एकमात्र यह नहीं है कि वे आना नहीं चाहते बल्कि यह है कि वहां स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करने, टैस्ट करने की सुविधाएं और आधुनिक उपकरण नहीं हैं। लोगों की आध्थक स्थिति ऐसी नहीं है कि बड़े शहरों में बीमारी का इलाज करवा सकें। यह सरकारी नीतियों की विफलता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डाक्टरों का बोलबाला और नीम हकीम खतरा–ए–जान की कहावत सिद्ध हो रही है। केवल जन स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान भारत और योग संस्थान की बदौलत लोगों की स्वास्थ्य रक्षा नहीं हो सकती। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके तीमारदारों की सच्ची कहानियां और सरकार की बेरुखी इस बात का प्रमाण हैं कि मैडीकल की पढ़ाई की व्यवस्था और गुणवत्ता प्रश्नों के घेरे में है।

ट्रम्प किसी भी रिश्ते को तोड़ और फैसला बदल सकते हैं

-सीमा सिरोही

क्या अमरीका–भारत टैरिफ समझौता एक साल की मानव निर्मित उथल–पुथल के बाद राजनीतिक विश्वास बहाल कर सकता है? इसका संक्षिप्त उत्तर है–कुछ हद तक। भारत–अमरीका के संयुक्त बयान में टैरिफ में जो कमी की गई है, ट्रम्प के रूसी तेल पर कार्यकारी आदेश ने उसे खत्म कर दिया है। कार्यकारी आदेश की भाषा, लहजा और विषयवस्तु, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू करने पर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की धमकी दी गई है, कम से कम दबावकारी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक है। यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल का आयात फिर से शुरू करता है, तो 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क फिर से लागू हो सकता है। भारत की ऊर्जा खरीद पर अपने अधिकार जताने के कारण ट्रम्प का रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन का नाम न लेना और उसे दंडित न करना, इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। राष्ट्रपति के आदेश में चीन का कोई जिक्र नहीं है। भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने से चीन को भारी छूट और अधिक मात्रा में तेल खरीदकर और भी अधिक लाभ हो रहा है। रूस पहले ही सऊदी अरब को पीछे छोड़कर चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता बन चुका है। अगर ट्रम्प को लगता है कि भारत पर दबाव डालने से पुतिन यूक्रेन में रियायतें देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो उन्होंने अभी तक मॉस्को को समझा नहीं है। ट्रम्प जो कर रहे हैं, उससे ऊर्जा खरीद एक भू–राजनीतिक खेल बन गया है और भारत का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि चीन को समग्र विजेता बनाया जा रहा है–और एक समय था जब चीन अमरीका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। भले ही भारत को टैरिफ में 18 प्रतिशत छूट की सबसे ज़्यादा जरूरत हो, लेकिन वाशिंगटन के साथ खोए हुए संबंधों को वापस पाने के लिए दिल्ली के लिए पुराने गौरवशाली दिनों में लौटना मुश्किल होगा। इसके अलावा, ट्रम्प के कारण दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में आई दरार को देखते हुए नीति निर्माता शायद ऐसा करना भी न चाहें। भारत में आलोचकों ने टैरिफ समझौते की निंदा करते हुए कहा है कि इसमें बहुत कुछ दिया गया है और कुछ लिया नहीं गया।

16 से 28 फरवरी तक चलेगा भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव

यूपी के 8 जिलों में होगा सांस्कृतिक उत्सव
भारत-नेपाल रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती-जयवीर

संवाददाता

लखनऊ। भारत–नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन 16 से 28 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में किया जाएगा। इस खास महोत्सव की शुरुआत 16–17 फरवरी को कुशीनगर से होगी, इसके बाद 18–19 फरवरी को सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम होंगे। महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और 27–28 फरवरी को पीलीभीत में अलग–अलग सांस्कृतिक आयोजन होंगे। यह महोत्सव भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का एक बड़ा प्रयास है।कुशीनगर के बुद्ध पीजी महाविद्यालय में 16–17 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित होंगे। 18–19 फरवरी को सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड में आयोजन किया जाएगा।

20 फरवरी को महाराजगंज के जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज में, 21 फरवरी को बलरामपुर के थारू जनजाति संग्रहालय इमलिया कोडर में और 22 फरवरी को श्रावस्ती के जगजीत इंटर कॉलेज में महोत्सव आयोजित होगा। 24 फरवरी को बहराइच के रामलीला ग्राउंड भीमराव अंबेडकर पार्क, सोनी बलईपुर में कार्यक्रम होगा। 26 फरवरी को लखीमपुर खीरी के राजकीय एकलव्य आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना परिसर में आयोजन किया जाएगा, जबकि 27–28 फरवरी को पीलीभीत के गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह में महोत्सव का समापन कार्यक्रम होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि, "यह महोत्सव दोनों देशों की साझा विरासत, परंपराओं और आपसी भाईचारे को मंच देने का काम करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीतेंगे और दोनों देशों के बीच सद्भाव का संदेश देंगे।''महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा, कवि सम्मेलन और संगोष्ठी शामिल हैं। "एक जनपद एक उत्पाद" की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत–नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित विशेष परिचर्चा, चित्रकला रंगोली प्रदर्शनी आयोजन का हिस्सा होंगी। प्रत्येक जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहयोग से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों को इस महोत्सव में सादर आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन न सिर्फ मनोरंजन का मौका देगा, बल्कि भारत–नेपाल की दोस्ती को और गहरा करने का अवसर बनेगा।

पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को हाथ-पैर पकड़कर टांगा

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी–डोनाल्ड ट्रंप के बीच कथित ट्रेड डील के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन उग्र होता कि उससे पहले ही पुलिस कार्यकर्ताओं को हाथ–पैर पकड़कर टांग लिया। उन्हें गाड़ी में भरकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष इरम रिजवी ने किया। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर एकत्र हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इरम रिजवी ने कहा कि यह समझौता देश के हितों के खिलाफ है और इससे स्थानीय उद्योग, कृषि और लघु व्यापार प्रभावित होंगे। इस डील की शर्तों को केंद्र सार्वजनिक करे और संसद में चर्चा करे। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों के नाम पर किसानों और व्यापारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। उनका आरोप था कि विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए घरेलू बाजार को कमजोर किया जा रहा है।कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर "किसान विरोधी डील वापस लो" और "व्यापारी विरोधी नीति नहीं चलेगी" जैसे नारे लगाए। मौके पर यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। आम आदमी पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को प्रदेशभर में तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में जिलास्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर एको गार्डन भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि प्रदर्शन की अनुमति निर्धारित शर्तों के तहत थी और कानून–व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है।

शंकराचार्य पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शाब्दिक हिंसा और पाप : अखिलेश यादव

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शाब्दिक हिंसा और पाप है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ–साथ उन्हें भी पाप लगेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सदन के बाहर जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। अखिलेश यादव की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में यह कहने के एक दिन बाद आई कि हर कोई शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता और सभी कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक मर्यादा और कानून का शासन बनाए रखा जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते, मुआवजा में भी भ्रष्टाचार निकाल लेते हैंय जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा, उसका हिसाब नहीं देतेय अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, ऐसे लोग किसी और के धर्म–पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। अखिलेश यादव ने कहा, अपने बयान में उन्होंने कानून का शासन बोल दिया। जैसे ही उनका ध्यान जाएगा, वे शविधि का शासन बोलने के लिए क्या फिर से सदन बुलाएंगे या टांग पर खड़े होकर लड़खड़ाता प्रायश्चित करेंगे। जब इंसान नहीं, अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वह व्यक्ति समाज में मान–सम्मान खो

देता है, जिसके बारे में कहावत प्रचलित है, जब मुंह खोला, तब बुरा बोला। सपा नेता ने कहा, हाता नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है। जिस समाज के खिलाफ उन्होंने हमेशा नफरत की राजनीति की है, उसे ध र्म के मामले में भी अपमानित–पराजित करने का यह उनका अहंकार है। अगर चाहें तो विवादित फिल्म का नाम बदले बिना ही रिलीज कर दें और कर मुक्त कर दें। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में समाज एक–एक वोट उनके खिलाफ डालकर अपने अपमान और प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देगा, उनकी सरकार हटाकर नई सरकार बनाएगा और फिर मिलजुलकर बेधड़क दाल–बाटी खाएगा। यादव ने कहा, शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इसे निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द भी निंदनीय महसूस होगा। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जिला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच हुए विवाद के लगभग एक महीने बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सभी आयोजनों में धार्मिक मर्यादा और कानून का पालन होना चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा, हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर कोई किसी पीठ का आचार्य होने का दावा नहीं कर सकता और माहौल खराब नहीं कर सकता। सभी को कुछ हद में रहना पड़ता है।

संक्षिप्त

जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में कैरियर काउंसिलिंग मेले का आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। समग्र शिक्षा (माध्यमिक) जिला परियोजना कार्यालय लखनऊ के द्वारा एक भव्य कैरियर काउंसिलिंग मेला का आयोजन राजकीय बालिका इण्टर कालेज, छोटी जुबिली में शनिवार को आयोजित किया गया। जिसमें अपने–अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने खेल, विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, कौशल विकास, चिकित्सा, प्रतियोगी परीक्षाओं जैस कैरियर विकल्पों में मार्गदर्शन प्रदान किया। मेंले में सैकड़ों की संख्या उपस्थित छात्राओं को अपने भविष्य में सही राह को चुनरने का मार्गदर्शन मिला। इस भव्य कैरियर काउंसिलिंग मेंले का उदघाटन उप–निदेशक माध्यमिक शिक्ष लखनऊ मंडल रेखा दिवाकर ने किया। इस अवसर पर राजकीय इंटर कालेजों के प्रधानाचार्य, शिक्षक,शिक्षिकायें तथा छात्र व छात्रायें उपस्थित थे। इस कैरियर काउंसिलिंग मेले का आयोजन जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार के मार्गदर्शन व जिला समन्वयक संतोष कुमार मिश्रा की देखरेख में सम्पन्न हुआ। अतिथियों का स्वागत जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया। उन्होने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास होला है। साथ ही उनकों अपने उज्जवल भविष्य की राह चुनने में आसानी होती है। कार्यक्रम का सफल संचालन शाजिया बानो तथा कुष्ण कुमार शुक्ला ने किया। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक मनीषा द्विवेदी,डा0 अंकिता सिंह, मनीष तिवारी, प्रवीण श्रीवास्तव, डा0 अनिता सिंह, पूनम शाही सहित अनेक अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

शादी से लौट रहे युवक की एक्सीडेंट में मौत,डिलीवरी बॉय ने पहुंचाया अस्पताल

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र के रहने वाले 28 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक आलमबाग में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था, तभी लंगड़ा फाटक के पास कोई वाहन उसकी बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गया। वह सड़क पर तड़प रहा था तो एक डिलीवरी बॉय ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन बचाया नहीं जा सका। कैंपल रोड स्थित रीफा कॉलोनी ठाकुरगंज निवासी नितिन कुमार (28) पुत्र ज्ञान प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में काम रहते थे। परिवार में मां प्रतिमा सिंह और छोटा भाई वैभव हैं। परिजनों के मुताबिक, नितिन शुक्रवार रात आलमबाग के होटल में शादी समारोह में शामिल होने गया था। रात में करीब 1 बजे वो वापस लौट रहा था।

होटल सेलेस्टियल मेनोर का विस्तार, तेलीबाग, वृंदावन में 4-स्टार सुविधाओं के साथ 'द आर्केडियम सेंट्रल' परियोजना की घोषणा

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ स्थित होटल सेलेस्टियल मेनोर ने अपने विस्तार की आधिकारिक घोषणा करते हुए तेलीबागदृवृंदावन क्षेत्र में नई प्रीमियम होटल परियोजना "द आर्केडियम सेंट्रल" प्रारंभ करने की जानकारी दी। यह परियोजना 4–स्टार मानकों के अनुरूप विकसित की जाएगी, जिसमें आधुनिक आतिथ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध ा में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार निवेश और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की ऐसी परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती हैं। उन्होंने इस पहल को क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। होटल सेलेस्टियल मेनोर के चेयरमैन मनीष वर्मा ने कहा कि "द आर्केडियम सेंट्रल" परियोजना आधुनिक सुविधाओं, उच्च सेवा मानकों और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि होटल उद्योग में बढ़ती मांग और लखनऊ के विस्तारित शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विस्तार की योजना बनाई गई है, ताकि ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान की जा सकें।नया होटल 136 सुसज्जित कमरों के साथ विकसित किया जाएगा। होटल में दो भव्य बैंक्वेट हॉल होंगेकृपहले बैंक्वेट हॉल की क्षमता 250 से 300 अतिथियों की होगी, जबकि दूसरे बैंक्वेट हॉल में 400 से 450 लोगों के एक साथ आयोजन की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार दोनों बैंक्वेट हॉल की कुल संयुक्त क्षमता एक समय में लगभग 800 से 900 अतिथियों तक होगी, जिससे बड़े सामाजिक, व्यावसायिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन सुगमता से किया जा सकेगा।136 कमरों के साथ दो भव्य बैंक्वेट हॉल, 800दृ900 अतिथियों की संयुक्त क्षमता वाला अत्याधुनिक होटल विकसित होगा। पूल, जिम और सैलून जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध। राशी इंफ्राटेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए तथा कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान की गरिमामयी उपस्थिति में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर डॉ. सौरभ सचान, वाइस चेयरमैन, दीनानाथ ग्रुप एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, आर्केडियम ने जानकारी दी कि परियोजना के विकास हेतु तैप प्दतिजमबी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है तथा गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान सुनिश्चित किया जाएगा।"द आर्केडियम सेंट्रल" परियोजना के माध्यम से होटल सेलेस्टियल मेनोर आतिथ्य क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए तेलीबाग वृंदावन क्षेत्र को एक नया प्रीमियम होटल डेस्टिनेशन देने की दिशा में अग्रसर है।

चलती बाइक पर युवक की गर्दन में उलझा चाइनीज मांझा

पत्नी–बेटे समेत फ्लाईओवर पर गिरा, पत्नी घायल

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा लोगों की जान पर बनता जा रहा है। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में शेर वाली कोठी के पास रहने वाले 29 वर्षीय मोहम्मद मुशर्रफ शनिवार को चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बाइक से हुसैनगंज से लालकुआं जा रहे थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही उनकी बाइक फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक चाइनीज मांझा सामने आ गया। मुशर्रफ संभल पाते उससे पहले मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। तेज धार मांझे से उनकी गर्दन कट गई और दर्द से घबराकर उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दी। बाइक स्लिप हो गई और तीनों फ्लाईओवर पर ही गिर पड़े। हादसे में मुशर्रफ गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। छोटी बच्ची बाल–बाल बच गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद की। मुशर्रफ और उनकी पत्नी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद मुशर्रफ की हालत स्थिर है। मुशर्रफ ने बताया मैं पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से लालकुआं जा रहा था। फ्लाईओवर पर मांझा गर्दन में फंस गया। इससे बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई। पत्नी और बच्ची समेत फ्लाईओवर पर गिर गया। गनीमत

रही कि फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरा या पीछे से आ रहे किसी वाहन की चपेट में नहीं आए, वरना बड़ा हादसा हो जाता। गिरने से पत्नी को भी चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। मुशर्रफ ने कहा प्रतिबंधित होने के बावजूद लोग चाइनीज मांझे का प्रयोग कर रहे हैं। यह जानलेवा बन रहा है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों की जान बच सके।

सीएम योगी ने गैस चैंबर से की दिल्ली के वायु गुणवत्ता की तुलना

कहा विकास के बाद भी यूपी में घुटन भरा माहौल नहीं

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की तुलना गैस चैंबर से करते हुए शनिवार को कहा कि उप्र में तेजी से विकास हो रहा है, इसके बावजूद घुटन भरा माहौल नहीं है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण नुकसान की है। उन्होंने कहा, आप देखिए यहां का पर्यावरण कितना अच्छा है, कोई प्रदूषण नहीं है। अगर प्रदूषण नहीं है, तो कोई बीमारी भी नहीं है। जब भी प्रदूषण होगा, तो यह फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा।

अगर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली मशीन खराब हो जाती है, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया में पुनःनिर्मित विकास अधिकारी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली में वायु गुणवत्ता मानक पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, आप दिल्ली जाइए। क्या हालत है? ऐसा लगता है कि वहां गैस चैंबर है। हालत खराब है। आप हवा में सांस नहीं ले पाएंगे और आंखों में जलन होगी। वहां के डॉक्टर का कहना है कि जिन्हें अस्थमा और दूसरी बीमारियां हैं, बुजुर्ग और बच्चे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या यही जिंदगी है? आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। उन्होंने कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि यहां विकास तो है, लेकिन दम घुटने वाला माहौल नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह नौ बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 214 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है।

यूपी की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ढाई गुना से ऊपर, 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी पहुंची 13 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के पीछे महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते नौ वर्षों में राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी दर 13 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। इसी अवधि में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्ष 2017 में करीब 13 लाख करोड़ रुपये तक सीमित रही जीएसडीपी 2026–27 में बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये की ओर अग्रसर है। महिला श्रम बल भागीदारी दर में हर 1 प्रतिशत की वृद्धि से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 0.5 से 1 प्रतिशत तक अतिरिक्त उछाल आता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत व्यवहार में साबित होता दिख रहा है। महिला कार्यबल बढ़ने से उत्पादन क्षमता, श्रम उत्पादकता और राज्य के टैक्स बेस तीनों में समानांतर विस्तार हुआ है।महिलाओं की आय बढ़ने से घरेलू उपभोग में वृद्धि हुई है, जिससे एमएसएमई गतिविधियों और सेवा क्षेत्र को लगातार गति मिल रही है। नीतिगत स्तर पर महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए उत्तर प्रदेश में आर्थिक भागीदारी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। यदि यही रफ्तार बनी रही तो उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रहेगी।

श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण में तेजी

382 करोड़ की योजना में 251.82 करोड़ की पहली किस्त जारी, लखनऊ में तीन, गौतमबुद्धनगर में चार और गाजियाबाद में एक का हो रहा निर्माण
प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 500, कुल 4,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ

संवाददाता

लखनऊ। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में आने वाली कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने आठ श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। कुल स्वीकृत धनराशि का 66 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में जारी किया जा चुका है। इससे निर्माण कार्य को गति मिली है। भारत सरकार की एसएएससीआई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए 382 करोड़ रूपये बका प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में सीएंडडीएस को इस परियोजना का कार्यदायी संस्थान नामित किया है। विभागीय स्तर पर भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। लखनऊ में तीन, गौतमबुद्धनगर में चार और गाजियाबाद में एक समेत कुल आठ छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 500 महिलाओं की होगी। इस प्रकार कुल 4,000 कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, भोजनालय, सामान्य बैठक कक्ष तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य यह है कि रोजगार के लिए शहरों में आने वाली महिलाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण मिल सके।गाजियाबाद के सूर्यनगर क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास के लिए अनुमति के लिए प्रक्रिया जारी है। प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त होते ही वहां भी निर्माण कार्य पूर्ण गति से शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न उद्योगों, सेवा क्षेत्रों, निजी संस्थानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो एफआईआर-योगी

पीड़ितों की सहायता में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं

संवाददाता

गोरखपुर/ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी। सीएम ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये निर्देश प्रशासन व पुलिस के अफसरों को दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। बोले, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

जनता दर्शन में कुछ मामले ऐसे भी आए थे, जिनमें यह शिकायत की गई कि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पता लगाकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। पीड़ितों की मदद में शिथिलता या लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की हीलाहवाली हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझ कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों पर योगी ने अपना स्नेह बरसाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर उन्होंने गोसेवा की। गायों और गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, देहरादून में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

बीएनई

देहरादून। एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, देहरादून में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 138 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में अतिथि के रूप में अभिभावकगण, विद्यालय के निदेशक महोदय एवं प्रधानाचार्या महोदया उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यशील मॉडल प्रदर्शित किए गए। अभिभावक अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने आए और विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्यशील मॉडलों तथा उनके भविष्यगत उपयोगों को जानकर अत्यंत प्रभावित हुए। विद्यार्थियों ने प्रत्येक मॉडल को पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाया तथा आगंतुकों के प्रश्नों का उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की गई, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ा। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव सिद्ध हुआ तथा भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो यह सुनिश्चित किया गया।

भारत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्यकुमार ने दी जानकारी

एजेंसी

कोलंबो। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अभिषेक शर्मा रविवार को कोलंबो में चिर–प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। दरअसल, विस्फोटक बल्लेबाज हाल ही में नामीबिया के खिलाफ मैच में भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। उन्हें पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। हालांकि, उन्हें छुट्टी मिल गई थी। अभिषेक की होगी वापसी टी20 विश्व कप के हाई–वोल्टेज मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि कर दी है कि इस मैच में अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। उन्होंने कहा, श्अगर आप सब चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेले तो हम उसे खिलाएंगे।श मौजूदा टूर्नामेंट में अभिषेक ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है। अमेरिका के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए थे। वहीं, नामीबिया के खिलाफ वह खराब स्वास्थ्य के कारण शामिल नहीं हुए। अब वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वापसी करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक का प्रदर्शन अभिषेक ने पिछले साल एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ दो टी20 मैचों में 31 और 74 रन बनाए थे, जबकि फाइनल में वह सिर्फ 5 रन पर आउट हुए थे। बावजूद इसके भारत ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। कम समय में अभिषेक शर्मा भारत के उभरते हुए टी20 सितारे बन गए हैं। 39 मैचों में 1297 रन बनाते हुए उन्होंने दो शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बनाया था।

विश्व पटल पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा में जाना है तो आडम्बर और ढोंग से बचना होगा : न्यायमूर्ति राजवीर सिंह

– सूचना क्रांति चुनौती भी है और सहयोग भी : सूचना आयुक्त राजेन्द्र सिंह
– जीवन में शिक्षा नहीं तो विभिन्न परेशानियाँ आती हैं : राजेन्द्र यादव

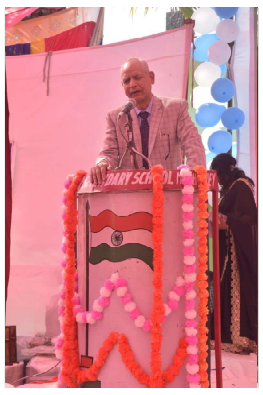

बीएनई

मूंढापांडे (मुरादाबाद)। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने कहा कि विश्व पटल पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा में जाना है तो आडम्बर और ढोंग से बचना होगा। आगे बढ़ने के लिए कोई सार्टकट रास्ता नहीं होता। बच्चों की शिक्षा कैसी हो स्कूल के साथ अभिभावकों का विशेष योगदान होता है। न्यायमूर्ति ने बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में बच्चों और अभिभावकों बताया कि उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े बच्चों के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, मूंढापांडे जैसे क्षेत्र का यह स्कूल इस रूप में कार्य कर रहा है कि विद्यार्थी विभिन्न विधाओं अपना भविष्य सुरक्षित करते हुए क्षेत्र और परिवार का नाम बड़ा रहे हैं। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह शुक्रवार को मूंढापांडे स्थित एम.जे.पी. इण्टर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कॉलेज के वार्षिकोत्सव के मुख्य वक्ता राज्य सूचना आयुक्त राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में विद्यार्थियों के लिए चुनौती भी है और सहयोग भी है। बड़े–छोटे शहर और क्षेत्र में अब कोई भेद नहीं रह गया है, जीवन में शिक्षा को लेकर जागरूकता है तो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाने का रास्ता साफ होता है। सूचना आयुक्त राजेन्द्र ने अभिभावकों को आगाह भी किया कि सूचना क्रांति में मोबाइल भविष्य सुरक्षित करने में तो बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है परन्तु यह क्रांति विद्यार्थियों के जीवन को खराब भी कर रही है, स्कूल और अभिभावकों द्वारा बहुत सतर्कता बरतनी होगी कि वह अच्छी सूचनाएं ही ग्रहण करें। उन्होंने आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के बारे में भी छात्र–छात्राओं को जागरूक किया। कुछ कटौती भले ही करनी पड़े तो करें, परन्तु उनकी शिक्षा अवश्य पूरी कराएं। मुरादाबाद जिले का यह क्षेत्र बहुत गौरवशाली है क्योंकि कई विधाओं में यहाँ के नागरिकों ने देश का नाम ऊँचा किया है। कॉलेज के

कॉलेज के वार्षिकोत्सव में विशिष्ट अतिथि सीबीआई बोर्ड (माध्यमिक) के निदेशक जीतेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जीवन में यदि शिक्षा नहीं है तो भविष्य सुरक्षित करने में विभिन्न तरीके की परेशानी आती है। अभिभावक अपने खर्चों में वार्षिकोत्सव में लखनऊ से आए विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव भारत सिंह ने उपस्थित छात्र–छात्राओं, अभिभावकों और क्षेत्रीय नागरिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल के सालाना आयोजन का इंतजार रहता है, वह समय आज है। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए भारत ने स्कूल प्रबन्धन आह्वान किया कि मूंढापांडे से निकलकर स्कूल के बच्चों की राजधानी में होने वाले विभिन्न आयोजनों और प्रतियोगिताओं में सहभागिता कराएं, इससे उनका बौद्धिक विकास होगा। शिक्षा के साथ–साथ जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए इसकी भी स्कूल से ही शिक्षित किया जाय। वार्षिकोत्सव में उपस्थित होने से पहले पहले न्यायमूर्ति राजवीर और राज्य सूचना आयुक्त राजेन्द्र सिंह, सीबीआई बोर्ड (माध्यमिक) के निदेशक द्वारा कॉलेज द्वारा नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन वकील साब द्वारा किया गया। कॉलेज के प्रबन्धक शमी ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उपस्थित विभागीय अधिकारियों से सहयोग की अपील भी किया। वार्षिकोत्सव में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक का मंचन किया। आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सत्तार, विधान परिषद में कार्यरत अधिकारी अशर, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नागरिक भी उपस्थित थे।

आत्मनिर्भर नहीं, ट्रंप पर निर्भर, अमेरिका से व्यापार समझौते पर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा

एजेंसी/नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वह अब ट्रंप पर निर्भर होती नजर आ रही है। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत की विदेश और आर्थिक नीतियों को अमेरिका के साथ संरेखित करने पर सहमति जताई है, जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कार्यकारी आदेशों का हवाला देते हुए संकेत दिया गया है कि यदि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखता है तो 25 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है।

जलवायु बचाने की लड़ाई में भारत की बड़ी कोशिश

खर्च बढ़कर जीडीपी का 5.6% हुआ, जानिए क्या बोलीं वित्त मंत्री

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के वैश्विक मंच से भारत ने जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में अपनी गंभीरता और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को साफ–साफ संदेश दिया दिया भारत क्लाइमेट एक्शन के लिए बाहरी वित्तपोषण का इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में भारत ने इस दिशा में अपना खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.6 प्रतिशत कर दिया है, जो देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता और निवेश में भारी उछाल एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने आंकड़ों के जरिए भारत की बदलती रणनीति को सामने रखा। उन्होंने कहा, ष्छह साल पहले, हम अपनी जीडीपी का लगभग 3.7 प्रतिशत क्लाइमेट एक्शन पर खर्च कर रहे थे। आज यह आंकड़ा बढ़कर 5.6 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने खुद निवेश किया है। उन्होंने विकसित देशों की ओर इशारा करते हुए कहा, ष्हम पैसे या तकनीक के कहीं और से आने का इंतजार नहीं कर रहे, हालांकि उन्हें आना चाहिएष्। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ग्लोबल साउथ लगातार क्लाइमेट फाइनेंसिंग में देरी का मुद्दा उठा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी श्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओंश का दो–तिहाई हिस्सा लक्ष्य तिथि से चार साल पहले ही हासिल कर लिया है। भविष्य की रूपरेखा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 में कार्बन कैप्चर रणनीतियों को वित्तपोषित किया गया है। इसका मकसद पूरे देश में इन रणनीतियों

को लागू करना है और इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जिन देशों में प्रदूषण में कम योगदान दिया उनके लिए क्लाइमेट एक्शन के लिए कम भुगतान वाजिब सीतारमण ने जलवायु कार्रवाई की लागत को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि जिन देशों ने प्रदूषण में कम योगदान दिया है, उन्हें क्लाइमेट एक्शन के लिए कम भुगतान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल उत्सर्जन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। ष्हमें लचीलेपन और अनुकूलन पर भी ध्यान देना होगा। अन्यथा, हमें बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, उन्होंने कहा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नहीं हो सकता कि कम उत्सर्जन करने वाले देशों को भी बराबर भुगतान करने के लिए कहा जाए; इसके लिए विभेदित उपचार की आवश्यकता है। वित्त मंत्री का यह बयान इस बात का संकेत है कि भारत जलवायु परिवर्तन को केवल मुद्दा नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत मान रहा है। जीडीपी के 5.6% का बड़ा निवेश और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों को बजट (2026–27) में शामिल करना यह साबित करता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल वादों को नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई को तरजीह दे रहा है।

यूरोप को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाकर खतरों से निपटने के लिए रहना होगा तैयार, बोले ब्रिटेन के PM स्टार्मर

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि यूरोप की रक्षा क्षमता और सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में शक्ति संतुलन का आधार सैन्य शक्ति बन गया है, इसलिए यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना होगा। यह बात उन्होंने 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही। इस अहम वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन में 60 से ज्यादा देशों और सरकारों के प्रमुख, लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष नेता व कम से कम 115 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यूरोप को क्या करने की जरूरत? स्टार्मर ने स्पष्ट कहा कि यूरोप को संभावित खतरों को रोकने में सक्षम होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने लोगों, मूल्यों और जीवन शैली की रक्षा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनके मुताबिक, यूरोप को सामूहिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी वकालत की। उन्होंने संकेत दिया कि ब्रिटेन को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां वह यूरोपीय संघ के सिंगल मार्केट के और करीब आ सकता है। स्टार्मर ब्रेक्जिट के छह वर्ष बाद संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि अब करीबी आर्थिक तालमेल पर नए सिरे से ध्यान देने का समय है और गहरा आर्थिक एकीकरण सभी पक्षों के हित में है। वहीं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी यूरोप और ब्रिटेन के बीच अधिक घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता

पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दोनों पक्षों को और करीब आना चाहिए। उनके अनुसार, ब्रेक्जिट के वर्षों बाद भी यूरोप और ब्रिटेन का भविष्य एक–दूसरे से जुड़ा हुआ है।

30 किमी समंदर फतह कर सात साल के रेयांश खामकर ने रचा इतिहास, बनाया विश्व रिकॉर्ड

एजेंसी

ठाणे। ठाणे के सात वर्षीय रेयांश खामकर ने अरब सागर की लहरों को चीरते हुए 30 किलोमीटर की ऐतिहासिक तैराकी पूरी कर विश्व पटल पर शहर और देश का नाम रोशन किया है। रेयांश ने 15 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालपे जेट्टी से विजयदुर्ग तक की दूरी महज 7 घंटे 30 मिनट 11 सेकंड में तय की। इस अद्भुत उपलब्धि के साथ उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। सात साल की उम्र में यह कारनामा कर रेयांश इस दूरी को तय करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे ठाणे शहर को गौरवान्वित कर दिया है। ठाणे की मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने रेयांश को सम्मानित करते हुए कहा कि यह पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा साहस, समर्पण और अनुशासन दुर्लभ है। रेयांश ठाणे नगर निगम के स्विमिंग पूल में कोच कैलाश अखाड़े के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करते हैं। उनकी मेहनत और निरंतर प्रशिक्षण ने ही इस सफलता की नींव रखी है। यह पहली बार नहीं है जब रेयांश ने रिकॉर्ड बनाया हो। महज छह साल की उम्र में उन्होंने 15 किलोमीटर की तैराकी कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था।

अपनी शादी के दिन कैसा महसूस कर रहे थे निक जोनस, बोले- जब प्रियंका मेरे सामने आई तो...

एजेंसी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के सबसे प्यारे और पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। वे हमेशा रोमांटिक पोस्ट और खूबसूरत तस्वीरों से कपल गोल्स सेट करते रहते हैं। उनकी शादी 2018 में हुई थी और उनकी एक चार साल की प्यारी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस है। हाल ही में निक ने अपनी शादी वाले दिन को लेकर कई खुलासे किए। शादी के दिन प्रियंका को देखकर कैसा हुआ महसूस हाल ही में निक जोनस ने जय शेट्टी के श्ऑन पर्पस पॉडकास्ट में अपनी शादी की बाते शेयर कीं। निक ने बताया कि जब प्रियंका शादी के दिन सीढ़ियों से नीचे उतरीं, तो उन्हें बहुत सुकून और शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वे बिल्कुल सही जगह पर हैं। शादी के दिन किस बात से घबराए थे निक? पॉडकास्ट में एक मजेदार गेम खेला गया, जिसमें निक को अनुमान लगाना था कि प्रियंका उनके बारे में क्या कहेंगी। जब पूछा गया कि प्रियंका के अनुसार शादी के दिन निक को सबसे ज्यादा किस बात की घबराहट थी?, तो निक ने पहले कहा कि उन्हें किसी बात की घबराहट नहीं थी। लेकिन फिर वे रुके और बोले, सच तो यह है कि शादी के दिन बहुत गर्मी थी। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं मुझे पसीना न आ जाए और मैं अजीब न लगूं। प्रियंका ने क्या कहा? जय शेट्टी ने प्रियंका का जवाब पढ़कर सुनाया। प्रियंका ने कहा कि निक बहुत आत्मविश्वास से भरे और शांत थे। उन्हें कभी घबराते नहीं देखा। दरअसल, प्रियंका और निक की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। निक ने रिश्ते के सिर्फ 3–4 दिन बाद ही प्रियंका को आई लव यू कह दिया था। प्रियंका को कब पता चला, निक ही उनके लिए सही हैं? निक ने कहा शायद जब वे पहली बार भारत गए थे, लेकिन प्रियंका ने कहा, जब निक ने उन्हें प्रपोज किया, तब उन्होंने हां कह दी। निक हंसते हुए बोले, ये तो बिल्कुल सही टाइमिंग थी। प्रियंका और निक की शादी दिसंबर 2018 में राजस्थान में हुई थी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743